रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062025-263917
CG-DL-E-17062025-263917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2652] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947
No. 2652] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

का.आ. 2717(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि नाभिकीय ईंधन और घटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा परमाणु उर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों में लगे हुए उद्योगों की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (का 14 1947) की पहली अनुसूची की मद 28 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5363(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा 28 दिसम्बर, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा की प्रास्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नाभिकीय ईंधन और घटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा परमाणु उर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों में लगे हुए उद्योगों की सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 जून 2025 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97-आईआर(पीएल)]
अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

S.O. 2717(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the Industry engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th December, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5363(E), dated the 11th December, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 28th June, 2025.

[F. No. S-11017/3 /97- IR(PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.06.17 22:32:40 +05'30'